



न्यूज़ब्रीफ

शिक्षकों के तौर पर काम करने वाली नन और पादरी आयकर छूट के हकदार हैं या नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार



नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है। सरकारी सहायता प्राप्त ईसाई मिशनरी स्कूलों में शिक्षक के तौर पर काम करने वाली नन और पादरी आयकर छूट के हकदार हैं या नहीं, इस पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है। प्रधान न्यायाधीश जैवाई चंद्रपूज, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार के इस कथन पर सज्जान लिया है कि इस मुद्दे पर तमिलनाडु और केरल के कई धर्मप्रांती और मंडलियों की याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। पीठ उस याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमत हो गई, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या शिक्षकों के रूप में काम करने वाली नन और पादरियों की आय पर आयकर लगाया जा सकता है। दिसंबर 2014 में आयकर विभाग ने शिक्षा अधिकारियों से शिक्षकों के तौर पर काम कर रहे लोगों के आय के स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) लगाने को कहा था। तमिलनाडु और केरल के लगभग 100 धर्मप्रांती और मंडलियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर उच्च न्यायालयों के सहमत नहीं होने के बाद शीर्ष अदालत में अपील दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि ननो और पादरियों की आय उस मंडली की आय बन जाती है जो स्कूल को चलाती है और ये शिक्षक व्यक्तिगत रूप से देतेन के रूप में भुगतान की गई राशि प्राप्त नहीं करते हैं।

रोजगार, समृद्धि व शांति के लिए निरंतर विकास जरूरी, डब्ल्यूईएफ में बोले विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा



नई दिल्ली । विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने विश्व आर्थिक मंच को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वैश्विक परिदृश्य को आकार देने में आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। बंगा ने जोर देकर कहा कि रोजगार सृजन, समृद्धि को बढ़ावा देने और शांति बनाए रखने के लिए निरंतर विकास जरूरी है। डब्ल्यूईएफ 24 सत्र में अपने मुख्य भाषण के दौरान, बंगा ने कहा, वास्तविकता यह है कि हम 30 वर्षों में सबसे कम विकास दर हासिल करने वाले दशक के पहले हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। विकास के बिना, आपके पास रोजगार नहीं होगी, आपके पास समृद्धि नहीं होगी, और अक्सर ऐसा होता है कि विकास के बिना, आपके पास शांति भी नहीं होती है। इसलिए मुझे लगता है कि निकट और मध्यम दोनों अवधि में विकास हमारी चुनौतियों के मूल में है। अपने संबोधन के दौरान बंगा ने निकट और मध्यम अवधि में वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली बहुमुखी चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

ईडी ने निर्माण कंपनी और उसके प्रवर्तकों के ठिकानों पर की छापेमारी, धनशोधन मामले में कार्रवाई



नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले में चेन्नई की निर्माण कंपनी, उसके प्रवर्तकों और उससे जुड़े लोगों के परिसरों पर धन शोधन मामले की जांच के लिए छापेमारी की। केंद्रीय एजेंसी ने ग्रेटर चेन्नई पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) की और से ऑसियन लाइफ़रपेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके एमडी और सीईओ एस्के पीटर, कुछ निदेशकों और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी का सज्जान लेने के बाद जांच शुरू की है। सूत्रों ने बताया कि चेन्नई शहर और उसके आसपास के करीब छह-सात स्थानों पर ईडी के अधिकारी धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जांच कर रहे हैं। सीसीबी ने पिछले साल कंपनी के पूर्व निदेशक बी श्रीराम की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि प्रवर्तकों ने उनके साथ धोखा किया और बाद में उन्होंने कंपनी के बोर्ड से अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का रुख किया।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। * फोन-0755-2550900-01,-03, फैक्स नं.- 0755-2553914 e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) रजिस्टर्ड नं.म.प्र./296/भोपाल/2012-2014 आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, डाक पंजीयन क्र. म.प्र./भोपाल/296/2015-2017

नईदुनिया

सेबी प्रमुख ने आईपीओ निवेशकों को किया सावधान बोलीं-ओवर सब्सक्रिप्शन दिखाने के लिए हो रही गड़बड़ी

उम्मीद से ज्यादा रह सकती है जीडीपी की रफ्तार बढ़ेगा सरकारी-निजी निवेश, आरबीआई लेख में दावा

मुंबई । भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में उम्मीद से ज्यादा मजबूत वृद्धि दर्ज कर सकती है। इसके साथ ही, सरकार और निजी क्षेत्र पूंजी निवेश पर ज्यादा जोर दे सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एक लेख में कहा गया है कि विश्व अर्थव्यवस्था को निकट भविष्य में विकास की अलग-अलग संभावनाओं का सामना करना पड़ रहा है। एशिया के नेतृत्व वाली उभरती अर्थव्यवस्थाएं बाकी दुनिया से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, यह लेखकों के अपने विचार हैं। लेख के मुताबिक, अर्थव्यवस्था ने 2023-24 में अब तक उम्मीद से अधिक मजबूत वृद्धि दर्ज की है। यह विकास दर खपत से निवेश की ओर बदलाव पर आधारित है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा के नेतृत्व वाली टीम के लेख में कहा गया है कि पूंजीगत खर्च पर सरकार का जोर निजी निवेश को बढ़ावा देने पर है।लेखकों ने कहा कि भारत में संभावित उत्पादन बढ़ रहा है। वास्तविक उत्पादन इससे ऊपर है। वित्त वर्ष 2024-25 में व्यापक आर्थिक स्थिरता के माहौल में कम से कम 7 फीसदी की वास्तविक जीडीपी वृद्धि हासिल करनी होगी। इससे विकास की तेज रफ्तार को बनाए रखने का उद्देश्य पूरा होगा। महंगाई को अगले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही तक लक्ष्य के अंदर लाने और उसी स्तर पर उसे स्थिर करने की जरूरत है। विकास को समर्थन देने के लिए वित्तीय स्थितियों को आसान बनाते हुए महंगाई पर काबू पाना होगा।

बैलेंसशीट और संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत - लेख के मुताबिक, वित्तीय संस्थानों की बैलेंसशीट को मजबूत करने के साथ संपत्ति की गुणवत्ता में और भी सुधार करने की जरूरत है। राजकोषीय और बाहरी संतुलन के चल रहे समेकन को जारी रखने की जरूरत है। तकनीकी परिवर्तन के लाभों का उपयोग एक अच्छे जोखिम-मुक्त वातावरण में समावेशी और सहभागी विकास के लिए किया जाना चाहिए।

निवेश में कॉरपोरेट क्षेत्र को बनाएं भारीदार - लेख के मुताबिक, इन सबसे ऊपर, सरकारी पूंजीगत खर्च से निवेश में कॉरपोरेट क्षेत्र को भारीदार बनाया जाना चाहिए। लेख में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि यदि देशों के बीच संघर्ष समाप्त हो जाए, क्मोडिटी के साथ वित्तीय बाजारों, व्यापार-परिवहन और आपूर्ति



2042 तक भारत को 2500 नए विमानों की जरूरत होगी, बोइंग ने एविएशन सेक्टर के बारे में की ये भविष्यवाणी

नई दिल्ली । हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारत को 2042 तक 2500 नए विमानों की जरूरत होगी। ये बातें बोइंग के कमर्शियल मार्केटिंग सेगमेंट के उपाध्यक्ष डैरेन हल्ट ने हैदराबाद में कही। हल्ट ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई यात्रियों और कार्गो की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, भारत को अगले दो दशकों में अपने बेड़े के आकार को चार गुना करना पड़ेगा। ऐसे में भारतीय विमानन कंपनियों को अपने बेड़े को पूरा करने के लिए 2,705 से अधिक नए विमानों की जरूरत होगी। उन्होंने कहा, 2042 तक इनमें से 92 प्रतिशत से अधिक (2,705 विमानों की जरूरत होगी) या 2,500 से अधिक विमानों की जरूरत होगी। यह पिछले साल के मध्य में दिए गए पूर्वानुमान पर आधारित है। उन्होंने कहा, हमारा अनुमान है कि यहां भारत सहित दक्षिण एशिया की विमानन कंपनियों को वर्ष 2042 तक 2,700 से अधिक विमानों की आपूर्ति की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा, विमानों के इस बेड़े में 2,300 से अधिक सिंगल बॉडी वाले जबकि लगभग 400 चौड़ी बॉडी वाले विमानों की जरूरत होगी। बोइंग के अनुसार, भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था और एशिया का एक बड़ा बाजार है जो एविएशन क्षेत्र की मांग के मामले में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के पहले के स्तर तक पहुंचने में सफल रहा है। यह दर्शाता है कि भारतीय बाजार में हवाई यात्रा किन्तनी महत्वपूर्ण है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने में बढ़ते हवाई यात्रियों की संख्या भी योगदान दे रही है।

नेटवर्क के माध्यम से उनके प्रभावों को नियंत्रित किया जाए, तो कमजोर वैश्विक दृष्टिकोण को अच्छा बनाया जा सकता है। रेटिंग एजेंसी इकना ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर छह फीसदी से नीचे रह सकती है। खरीफ फसलों के

उत्पादन में कमी और रबी में कुछ फसलों की कमजोर बुवाई का असर जीडीपी की वृद्धि पर दिखेगा। दूसरी तिमाही में देश की वृद्धि दर 7.6 फीसदी रही थी। इसका कहना है कि कुछ गतिविधियों में लगातार दूसरे महीने सुस्ती दिख रही है।

जियो के तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित: कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़कर 5,208 करोड़ रहा, रेवेन्यू 10 प्रतिशत बढ़ा

मुंबई। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने फाइनैशियल ईयर 2023-24 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जियो का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़कर 5,208 करोड़ रुपए रहा।

कंपनी ने पिछले साल समान तिमाही में 4,638 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। वहीं पिछले तिमाही यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट 5,058 करोड़ रहा था। जियो का नेट प्रॉफिट तिमाही आधार पर 3 प्रतिशत बढ़ा है।

जियो का रेवेन्यू 10 प्रतिशत बढ़कर 25,368 करोड़ रहा

ऑपरेशंस से कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 10 प्रतिशत बढ़कर 25,368 करोड़ रुपए हो गया। पिछले फाइनैशियल ईयर की इसी अवधि में ये 22,998 करोड़ रुपए रहा था। वहीं पिछली तिमाही में



कंपनी का रेवेन्यू 24,750 करोड़ रुपए रहा था। इस हिसाब से में कंपनी का रेवेन्यू तिमाही आधार पर 2.5 प्रतिशत बढ़ा है।

एबीतडा दिसंबर तिमाही में 13,277 करोड़ रहा

जियो इंफोकॉम का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 13,277 करोड़ रुपए रहा। यह इसके ठीक पिछली तिमाही में रहे 12,953 करोड़ रुपए के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से 2.5 प्रतिशत ज्यादा है। जियो का एबीतडा मार्जिन दिसंबर तिमाही में 52.3 प्रतिशत रहा। वहीं पिछली तिमाही में कंपनी का एबीतडा मार्जिन 52.3 प्रतिशत ही रहा था।

पेसिको ने जागृत कोटेजा को अपना नया इंडिया चीफ बनाया, इस चिप्स को लॉन्च करने में था अहम योगदान

नई दिल्ली । पेसिको इंडिया ने एक गतिशील और आगे की सोच वाले वैश्विक दृष्टिकोण के तहत भारत में नए नेतृत्व का एलान किया है। खाद्य और पेय निर्माता कंपनी ने पेसिको अफ्रीका, मध्य-पूर्व और दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी जागृत कोटेचा को अपना भारत में अपना सीईओ बनाया है। यह कदम कंपनी के निवर्तमान मुख्य कार्यकारी अहमद अल शेख को मध्य पूर्व शाखा की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद उठाया गया है। उनका भारतीय टीम के साथ सात साल लंबा कार्यकाल रहा।

कंपनी ने कहा कि यह निर्णय एएमईएसए में नेतृत्व परिवर्तन की शृंखला के एक हिस्से के रूप में उठाया गया है और कल भारतीय कर्मचारियों को इस बारे में सूचित किया गया।

पेसिको के प्रवक्ता ने कहा, भारत पेसिको के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है और हमारी वैश्विक रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले छह वर्षों में, अहमद हमारे व्यवसाय को बदलने, नवाचार का कार्यान्वयन करने और चुनौतीपूर्ण परिदृश्य के माध्यम से टीम का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अफ्रीका, मध्य-पूर्व और दक्षिण एशिया के सीईओ यूजीन विलेम्स ने



एक बयान में कहा, मैं भारत की कार्यकारी टीम में जागृत का स्वागत करता हूं और मुझे यकीन है कि हम अपने भारतीय उपभोक्ताओं के बीच जागृत के नेतृत्व में सफलता के नए शिखर हासिल करेंगे।

1994 में कंपनी से जुड़े कोटेचा के पास विक्री और ब्रांड प्रबंधक के रूप में काम करने का व्यापक अनुभव है और उन्होंने एंड-टू-एंड लाभ और हानि (पीएंडएल) जिम्मेदारी संभाली है। उन्होंने 2018 में पेसिको इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में कंपनी के उत्पादों लेज और कुरकुरे के इन्वेंशन और

ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया को देखरेख की थी। कंपनी के इस कदम का उद्देश्य अपने उत्पादों को भारतीय उपभोक्ताओं के लिए बेहतर और अनुकूल बनाना था। उन्होंने 2017 में एक और सैक्रे, ज़ोरिटोस की लॉन्चिंग का भी नेतृत्व किया था।

अमेरिका कंपनी पेसिको ने हैदराबाद में अपने वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र का विस्तार करने का भी फैसला किया है, कंपनी का लक्ष्य के के 250 कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाकर 4,000 कर्मचारियों तक करना है।



गूगल में एक बार फिर हो सकती है कर्मचारियों की छंटनी, सीईओ सुंदर पिचाई ने कर्मियों को किया अलर्ट

वाशिंगटन । दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल ने बड़ा एलान किया है। गूगल के सीईओ ने अपने कर्मचारियों से कहा कि आप इस साल और अधिक छंटनी के लिए तैयार रहें। बता दें, यह पहली बार नहीं है जब गूगल अपने कर्मियों को निकालने के लिए कह रहा है। कंपनी पहले भी कई बार अपने कर्मियों को निकाल चुका है।

आंतरिक मेल से कर्मचारियों को दी गई जानकारी

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के एक आंतरिक मेल में कहा गया है कि गूगल विभिन्न विभागों में अभी हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकता है। मेल के माध्यम से पिचाई ने कर्मचारियों से कहा कि कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं, जिनके लिए इस प्राथमिकताओं के आधार पर निवेश किया जाएगा। निवेश की यह शक्ति हासिल करने के लिए कंपनी को कठोर विकल्प चुनने होंगे। हालांकि, पिचाई का कहना है कि यह कटौती हर टीम को प्रभावित नहीं करेगी। पिचाई ने कहा कि वे जानते हैं कि कुछ सहकर्मियों और

छंटनी की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने सैकड़ों कर्मचारियों को निकाल दिया था। पिछले साल भी जनवरी में ही अल्फाबेट ने 12,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। इस फैसले के कारण अल्फाबेट के कर्मचारियों के आकड़ों में छह प्रतिशत की गिरवाट दर्ज की गई थी। एक प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट की मानें तो गूगल 2024 की शुरुआत में ही करीब 1000 लोगों को बर्खास्त कर चुकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी अब इन कर्मचारियों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल करेगी।

रोजगार वाले क्षेत्रों के लिए आ सकती है पीएलआई, कपड़ा-हस्तशिल्प को किया जा सकता है शामिल

नई दिल्ली । विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और रोजगार में वृद्धि के लिए सरकार अंतिम बजट में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का दायरा बढ़ा सकती है। डेलॉय ने कहा, कपड़ा, आभूषण और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों को भी पीएलआई के दायरे में शामिल किया जा सकता है। डेलॉय इंडिया के पार्टनर राजत वाही ने कहा, पीएलआई योजना के तहत 14 क्षेत्र हैं। इनमें से कई क्षेत्र बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा नहीं करते हैं। कम आय वाले परिवारों के साथ शहरी लोगों को भी लाभ डेलॉय ने कहा, चमड़ा, परिधान, हस्तशिल्प व आभूषण जैसे कई क्षेत्रों को योजना के दायरे में लाने की जरूरत है। ये क्षेत्र रोजगार के सबसे अधिक अवसर पैदा करते हैं। इन्हें योजना के दायरे में लाने से कम आय वाले परिवारों के साथ शहरी लोगों को भी मदद मिलेगी। ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए करने होंगे उपाय डेलॉय ने बजट अपेक्षा रिपोर्ट में कहा, सरकार से ग्रामीण परिवारों की आय में सतत वृद्धि के उपाय करने की उम्मीद है। ग्रामीण आय बढ़ाकर महंगाई और उपभोग मांग में कमी से निपटा जा सकता है। वित्त मंत्री एक फरवरी, 2024 को अंतिम बजट पेश करेंगी।



नई दिल्ली । भारत स्वर्ण भंडार के मामले में सऊदी अरब, ब्रिटेन और स्पेन जैसे देशों से काफी आगे है। इन देशों की तुलना में भारत के पास 519.2 टन तक अधिक सोने का भंडार है। फोर्ब्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, सोने के भंडार के लिहाज से शीर्ष-20 देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर है। इसके पास 2023 की तीसरी तिमाही तक 800.78 टन सोने का भंडार है। यह सूची में 16वें स्थान पर काबिज सऊदी अरब के 323.07 टन के सोने के भंडार से 477.71 टन, 17वें स्थान पर काबिज ब्रिटेन के 310.29 टन से 490.49 टन व 20वें स्थान वाले स्पेन के 281.58 टन से 519.2 टन अधिक है।

सऊदी अरब के पास 323.07 टन व ब्रिटेन के पास 310.29 टन भंडार

देशों के स्वर्ण भंडार बनाए रखने के कई कारण हैं। सोने को मूल्य के एक स्थिर और भरोसेमंद भंडार के रूप में पहचाना जाता है। वैश्विक अनिश्चितता के दौर में सोना आर्थिक स्थिरता के प्रति भारोसा पैदा करता है। साथ ही, यह ऐतिहासिक रूप से किसी देश की मुद्रा के मूल्य का समर्थन करने में योगदान देता है। फोर्ब्स ने कहा कि टैंजिबल एसेट्स होने के नाते सोने को अपने भंडार में रखकर कोईभी देश पोर्टफोलियो में विविधता लाने का काम करते हैं।यही विविधता अन्य एसेट्स के मूल्य में उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों को कम करने में भी मदद करता है। कुछ देश व्यापार असंतुलन को नियटाने या कर्ज लेने के लिए सोने का इस्तेमाल करते हैं।

शीर्ष-10 देशों में अमेरिका सबसे आगे

- अमेरिका- 8,133.46 टन
- जर्मनी- 3,352.65 टन
- इटली- 2,451.84 टन
- फ्रांस- 2,436.88 टन
- रूस- 2,332.74 टन
- चीन- 2,191.53 टन
- स्विट्जरलैंड- 1,040.00 टन

- जापान- 845.97 टन
- भारत- 800.78 टन
- नीदरलैंड- 612.45 टन